बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन (1990-2020): जनता दल (यूनाइटेड) के विशेष संदर्भ में

राजनीति विज्ञान में पी-एचडी की उपाधि प्राप्त करने हेतु

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार को प्रस्तुत

प्रस्तावित शोध कार्य

2024

पर्यवेक्षक

शोधार्थी

संजय कुमार सुमन

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग

आर.बी. कॉलेज, दलसिंहसराय, समस्तीपुर

पिन कोड 848114

बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन (1990-2020): जनता दल (यूनाइटेड) के विशेष संदर्भ में

परिचय

भारत में राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति है जो विभिन्न स्तरों- स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे क्षेत्रीय पार्टियाँ राष्ट्रीय राजनीति में अधिक मुखर होती जा रही थीं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के बीच अंतर तेज़ी से कम होता जा रहा था। कई राज्य-स्तरीय पार्टियों के उदय ने किसी भी एक पार्टी के लिए निचले सदन में बहुमत सीटें हासिल करना मुश्किल बना दिया है। इसने गठबंधन राजनीति के युग की शुरुआत की, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया। इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्र सरकार पर उनके हितों को पहचानने के लिए दबाव डाला है जिससे केंद्र सरकार कमजोर हो गई है।

बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए बिहार की राजनीति को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया गया है जो राज्य में राजनीति की एक अलग परिघटना को परिभाषित करता है। आज़ादी से लेकर प्रथम चरण चार दशकों में से 1951 से 1990 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। दूसरा 15 वर्षों का चरण (1990-1997 और 1997-2005), जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित था, जिसके प्रमुख राजनीतिक अभिनेता लालू प्रसाद यादव थे। बिहार की राजनीति का तीसरा और मौजूदा दौर जो आज तक जारी है, शुरू होता है अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में जद (यू)-भाजपा गठबंधन की जीत। मुख्य रूप से तीन चरण बिहार की राजनीति सरकार और शासन के तीन अलग-अलग प्रतिमानों को दर्शाती है । राज्य की राजनीति के पहले चरण में ऊंची जाति का दबदबा था । बिहार में कांग्रेस का 40 साल का शासन था । 1990 तक कांग्रेस पार्टी का यह

चरण पार्टी ढांचे के भीतर के संघर्ष को भी दर्शाता है कांग्रेस, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लगातार मुख्यमंत्री बदले गए । श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसका कांग्रेस शासन में उनका पूरा कार्यकाल पूरा हो सका, श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद, जनता दल के यह लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया ।

1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव : इमरजेंसी के विरोध में जब देश में मंडल आंदोलन की लहर थी और दूसरी ओर बीजेपी कमंडल की राजनीति को धार देने में जुटी थी । लेकिन कांग्रेस विरोध के मामले पर दोनों एकजुट थे । केंद्र में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की सरकार चल रही थी और बीजेपी का समर्थन उसे हासिल था । इसी बीच बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ. तब झारखंड का हिस्सा भी बिहार राज्य में ही था । 324 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिलीं । बहुमत के लिए कम से कम 163 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी । जनता दल को 122 सीटें मिलीं, लेकिन बहुमत के लिए उसे और सीटों की जरूरत थी । बीजेपी के 39 विधायक जीतकर पहुंचे थे । केंद्र की वीपी सिंह सरकार की तर्ज पर बीजेपी ने बिहार में भी जनता दल सरकार को समर्थन दिया । जनता दल में चली रस्साकस्सी के बीच पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास को हराकर लालू यादव नेता चुने गए । 10 मार्च 1990 को लालू पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे । इसी के साथ लालू ने बिहार में कांग्रेस पार्टी के शासन का खात्मा कर दिया ।

बिहार की राजनीति का दूसरा चरण जनता दल के उदय के साथ राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाता है । इसी दौर में एक करिश्माई नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ जो क्रमशः दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने । बिहार की राजनीति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का प्रभाव जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी संरचना में राजनीति देखी जा सकती है ध्यातव्य है की इसी काल में लालू प्रसाद यादव पर 'चारा घोटाले'

का आरोप लगा जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा परिणामस्वरूप देश के सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर एक अशिक्षित महिला को मिला ।

राज्य की राजनीति का तीसरा चरण अक्टूबर, 2005 विधानसभा चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन की जीत के साथ शुरू होता है. जिसमें नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बनकर उभरे राज्य और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रारम्भ में नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था सुधारने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया एवं बाद में इसके साथ-साथ आर्थिक समृद्धि को सुदृढ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके परिणमस्वरूप राज्य में आर्थिक-सामाजिक समृद्धि लाई एवं उनके इस प्रयास के कारण उन्हें 'सुशासन कुमार' कहा जाता है । कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने 2010 के विधानसभा चुनाव को जाति बनाम विकास के रूप में लड़ा गया चुनाव बताया है जो इस राज्य की राजनीतिक संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था । ज्ञात हो बिहार की राजनीति में एक मोड़ यह भी आया कि जद (यू) राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ जिसे कई कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा बिहार की राज्य राजनीति में 'प्रतिमान परिवर्तन' के रूप में संदर्भित किया गया ।

2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इन दलों के द्वारा महागठबंधन का निर्माण किया गया इस महागठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हरा दिया हालाँकि राज्य में सरकार लेकिन दो साल के शासन के उपरांत 2017 में नीतीश कुमार ने फैसला किया वे अपने पुराने सहयोगी दल बीजेपी के पास वापस जाएंगे ।

राजनीतिक दलों को आम तौर पर राजनीतिक जीवन में एक आवश्यक कारक के रूप में पहचाना जाता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि राजनीतिक दल एक सार्वभौमिक परिघटना बन गया है। वर्तमान में एक देश को एकल-दलीय मॉडल, द्वि-दलीय मॉडल, या बहुदलीय मॉडल या उनके एक अजीब मिश्रण में ढाला जा सकता है। मौरिस डुवर्गर, सिगमंड न्यूमैन, लॉर्ड ब्राइस

और कई अन्य जैसे प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों ने तटस्थता की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ बड़े या छोटे राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और विकास का पता 1688 की गौरवशाली क्रांति से इंग्लैंड में लगाया जा सकता है। इसलिए, ब्रिटिश पार्टी प्रणाली दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों में राजनीतिक दलों के विकास के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक दल को कुछ सिद्धांतों के समर्थन में एक संगठित समूह या संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। राजनीतिक दल को कुछ उद्देश्यों के साथ एक निकाय का गठन करने वाले नागरिकों के समूह के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यहां विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई राजनीतिक दल की कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं।

मैकाइवर के अनुसार, "राजनीतिक दल किसी सिद्धांत या नीति के समर्थन में संगठित एक संघ है जो संवैधानिक तरीकों से सरकारों को निर्धारक बनाने का प्रयास करता है।" हरमन फाइनर परिभाषित करते हैं कि "राजनीतिक एक संगठित निकाय है जिसमें स्वैच्छिक सदस्यता होती है, इसकी ठोस ऊर्जा राजनीतिक शक्ति की खोज में नियोजित होती है।" सिगमंड न्यूमैन की परिभाषा है कि "राजनीतिक दल समाज के सक्रिय राजनीतिक परिवर्तनों का स्पष्ट संगठन है, जो सरकारी सत्ता के नियंत्रण से चिंतित हैं और जो दूसरे समूह या भिन्न विचार रखने वाले समूहों के साथ लोकप्रिय समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।"

"क्षेत्रीय पार्टियों का उदय स्वतंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास में से एक रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विशेष क्षेत्रीय दलों पर कई काम किए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के उदय के पीछे के कारकों और उनकी केंद्रीय भूमिका का विश्लेषण करने के कुछ प्रयास किए गए हैं।" भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय एक जटिल और बहुआयामी घटना रही है और इसे केवल क्षेत्रवाद के परिणाम या उप-उत्पाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अपने अधिकारों पर घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल विविधता वाले

देश में, जहां राजनीतिक तरलता अनिश्चित काल तक जारी रहती है, कई छोटी पार्टियां या विशुद्ध रूप से स्थानीय या क्षेत्रीय मूल की पार्टियां स्थानीय मुद्दों के साथ उभरी हैं। भारत का चुनाव आयोग (ECI), चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 'राष्ट्रीय' या 'राज्य दलों' के रूप में मान्यता देता है। यह निर्धारित करने के मानदंड कि कोई पार्टी राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय, भारत में दो कारक शामिल हैं: (1) उन राज्यों की संख्या जहां उसे लोकप्रिय चुनावी समर्थन प्राप्त है और (2) राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसे मिले वोटों का प्रतिशत। . पहला मापदंड क्षेत्रीय है और दूसरा मापदंड पार्टी की लोकप्रियता से जुड़ा है. इसके अलावा, "कुछ विद्वान किसी क्षेत्रीय पार्टी की पहचान उसकी जातीयता या धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर करना चाहते हैं"।

"गठबंधन' शब्द जैसा कि आम तौर पर राजनीति विज्ञान में उपयोग किया जाता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली की अनिवार्यताओं का प्रत्यक्ष वंशज है"। गठबंधन की राजनीति को बहुदलीय सरकार के एक प्रकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें चुनाव में किसी एक पार्टी को आवश्यक बहुमत न मिलने पर कई पार्टियाँ सरकार चलाने के उद्देश्य से हाथ मिलाती हैं। "गठबंधन सरकार विषम सामाजिक-राजनीतिक तत्वों का एक संयोजन है जो बदलती सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों और मजबूरियों से उभरने वाले राजनीतिक उथल-पुथल और तूफानों के प्रति संवेदनशील होती है"। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 1977 तक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर एक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शासित या शासित थी। हालाँकि 1967 के बाद कांग्रेस ने कुछ राज्यों में सत्ता खो दी लेकिन बड़े पैमाने पर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली बनी रही। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का पहला अनुभव 1977 में देखने को मिला जब गैर-कांग्रेसी ताकतें जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एकजुट हुईं। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता पार्टी सरकार से हार गई और मोरारजी

देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री बने। तब से गठबंधन राजनीति भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया लेकिन फिर भी एनडीए के सहयोगी दलों के सदस्यों को महत्वपूर्ण विभाग देने का फैसला किया।

गठबंधन की राजनीति ने न केवल राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है बल्कि राज्य की राजनीति ने भी राज्य में सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रहने के लिए क्रमशः यही पैटर्न अपनाया है। बिहार का मामला भारत में ऐसी गठबंधन राजनीति का एक उदाहरण है।

अध्ययन का औचित्य

जद (यू) की उत्पत्ति, सामाजिक आधार, नेतृत्व संरचना, विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियां और चुनावी प्रदर्शन अध्ययन का विषय है। जद (यू) का गठन बिहार में राजद और लालू-राबड़ी शासन को चुनौती देने और बदलने के लिए किया गया था, जिसे अक्सर 'जंगल राज' कहा जाता था। 1994 में जनता दल छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों और सबक को भूलने का आरोप लगाया क्योंकि वह गांधी मैदान में बिहार के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहे थे, 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद। यह अध्ययन 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित शासन के मॉडल की जांच करना चाहता है जो राज्य में लालू-राबड़ी शासन से अलग है। पार्टी संरचना में अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए लालू प्रसाद यादव की अक्सर आलोचना की जाती थी। यह अध्ययन राज्य में जद (यू)-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सामाजिक आधार के रूप में जाति की भूमिका की भी समीक्षा करता है। मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार को 'सुशासन कुमार' का नाम दिया गया था। यह अध्ययन 2004 से 2020 तक राज्य

में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार आदि के मुद्दे से निपटने के लिए जद (यू) के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा अपनाए गए विकास मॉडल की जांच करता है।

आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव राज्य में शासन की प्रकृति तय करते हैं। . इसलिए यह अध्ययन 2004 से 2020 तक जद (यू) के चुनावी प्रदर्शन की भी जांच करता है और राज्य में जद (यू)-भाजपा गठबंधन की चुनावी जीत के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन के माध्यम से, अध्ययन विभिन्न चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के चश्मे से जाति और विकास की भूमिका को परिभाषित करने का प्रयास करता है। अंत में यह अध्ययन राज्य के मुख्यमंत्री और जद (यू) के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार की भूमिका का पता लगाता है।

साहित्य की समीक्षा

सामान्य तौर पर लोकतंत्र और विशेष रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र का सफल संचालन मोटे तौर पर राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। "राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती" हालाँकि, दुनिया भर में कई राजनीतिक और सामाजिक विचारकों ने पार्टी रहित लोकतंत्र की बात की है और इसका समर्थन किया है, लेकिन दुनिया भर में समकालीन राजनीतिक शासन में इसे शायद ही कोई स्वीकृति मिली है। "राजनीति के उप क्षेत्रों, उदाहरण के लिए भारतीय राज्यों में पार्टियों और पार्टी प्रणालियों का संगठित अध्ययन 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुआ, जिसमें मायरोन वेनर और इकबाल नारायण द्वारा दो सामूहिक खंड शामिल थे, जो पहली बार एक व्यापक इतिहास प्रदान करते थे। कई राज्यों के कार्य, उनकी पार्टी प्रणाली, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना और नेतृत्व के पैटर्न आदि" ।

विशेष राज्यों की राजनीति पर व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा कई अध्ययन किए गए। "जबकि ज़ोया हसन और पॉल ब्रास ने उत्तर प्रदेश पर अपना अध्ययन किया, जेम्स मैनर ने कर्नाटक की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। इसी प्रकार जयनत लेले और थॉमस ब्लॉम हसनसेन ने

जहां महाराष्ट्र की राजनीति का अध्ययन किया, वहीं घाना के श्याम शाह और बलदेव राज नैय्यर आदि ने गुजरात पर ध्यान केंद्रित किया।" "1980 के दशक की शुरुआत में जॉन आर. वुड्स द्वारा राज्य की राजनीति पर सामूहिक खंड स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय से राज्य स्तर की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक स्वतंत्र राजनीतिक स्थान को स्वीकार करने को दर्शाता है। यह बदलाव 1980 और 1990 के दशक के दौरान भारतीय राजनीति पर किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययनों में दिखाई देता है।

"अतुल कोहली गरीबी उन्मूलन के संबंध में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विभिन्न पार्टी शासनों की प्रभावशीलता पर अध्ययन करते हैं"। अतुल कोहली ने अपने तुलनात्मक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि "विभिन्न राज्यों के राजनीतिक शासनों के बीच मतभेद महत्वपूर्ण अंतर पैदा करते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में गरीब-समर्थक नीतियों को अपनाने में"। "हालाँकि, 'एक पार्टी के प्रभुत्व' की उनकी रूपरेखा सभी राज्यों के अनुकूल नहीं थी और इसके अलावा, राज्यों में एक पार्टी के प्रभुत्व के स्वरूप और पदार्थों का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन नहीं किया गया था"।

1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय और राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर गठबंधन सरकार का गठन एक और महत्वपूर्ण विकास बन गया जिसने कई विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ राज्यों में गठबंधन सहयोगी के रूप में क्षेत्रीय दलों के विकास और सत्ता में भागीदारी ने क्षेत्रीय दलों की वैधता के साथ-साथ उनके अध्ययन के महत्व को भी बढ़ा दिया है। "राज्यों में गठबंधन सरकारें उनके कामकाज की प्रकृति से जुड़े मुद्दों के परिप्रेक्ष्य से अध्ययन कर रही थीं" । "लेकिन इन अध्ययनों में क्षेत्रीय दलों का उनके अंतर-क्षेत्रीय असंतुलन और प्रासंगिक आयाम के परिप्रेक्ष्य से कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया"। "इ। श्रीधरन ने भारत में बहुदलीय अल्पसंख्यक सरकारों की प्रासंगिकता का अध्ययन किया है और स्वतंत्रता के बाद से गठबंधन की राजनीति की प्रकृति को परिभाषित किया है" । ई. श्रीधरन ने 1996 के बाद से भारत में

15/4/24

15/4/24

सभी गठबंधनों को अंतर-राज्य क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में परिभाषित किया है जो विभिन्न राज्यों में स्थित पार्टियों के बीच है। उनके विचार में 1991 के बाद की अवधि में विचारधारा (बीएचपी-शिवसेना) पर आधारित और तीन प्रकार की क्षेत्रीय अनुकूलता पर आधारित अंतर-राज्य गठबंधन भी देखा गया है। "तीनों में से, पहला अंतर-राज्य गठबंधन है जिसमें क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करती है और पूर्व को लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों की अधिकांश सीटें मिलती हैं"। "दूसरा पहले पैटर्न के विपरीत है, अर्थात, एक छोटी राज्य पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी के बीच गठबंधन। तीसरा प्रकार अंतर-राज्य गठबंधन है जिसमें क्षेत्रीय पार्टी कम लोकसभा सीटों और अधिक राज्य विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और इसकी राष्ट्रीय पार्टी सहयोगी इसके विपरीत (भाजपा-शिवसेना) लड़ती है। गठबंधन का स्पष्ट जोर वैचारिक अनुकूलता की कीमत पर भी क्षेत्रीय अनुकूलता पर रहा है, विशेष रूप से 1998, 1999 और 2004 का भाजपा गठबंधन और 2004 और 2009 का कांग्रेस गठबंधन, बल्कि 1996 का संयुक्त मोर्चा (यूएफ) गठबंधन भी ।

इसी प्रकार संजय कुमार ने बिहार में गठबंधन की राजनीति को 'एकदलीय प्रभुत्व से द्विध्रुवीयता से अनिश्चितता' तक परिभाषित किया है। उन्होंने भारत में गठबंधन राजनीति के उद्भव के लिए जिम्मेदार दो कारकों का प्रस्ताव रखा। पहला, राज्य दलों का उदय, जिन्हें आम तौर पर क्षेत्रीय दल कहा जाता है और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का पतन, जो कुछ अपवादों को छोड़कर 1990 के दशक की शुरुआत तक एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी रही। वह बहुदलीय प्रतियोगिता के युग में भारतीय राजनीतिक स्थिति में गठबंधन राजनीति को अपरिहार्य बताते हैं। 'बिहार में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1967 के वर्ष में देखी जा सकती है, जिसे संजय कुमार ने बिहार की राजनीति के दूसरे चरण के रूप में परिभाषित किया है', पहला चरण 1952-1967 तक था, जिसमें लगभग एकल-दलीय बहुमत का वर्चस्व देखा गया था। कांग्रेस। उनके विचार में दूसरा चरण अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित था, जिसमें लगभग छह वर्षों की अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों की नौ सरकारें बनीं। संजय कुमार 1990 के

दशक के शुरुआती चरण को जनता दल के तहत कांग्रेस विरोधी ताकतों के एकजुट होने का चरण मानते हैं, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के चरण को उन्होंने राज्य की राजनीति में कांग्रेस विरोधी ताकतों के विभाजन द्वारा चिह्नित एक नए चरण के रूप में देखा। 1997 से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जनता दल और बाद में राजद ने गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया है।

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का उदय 1996 के संसदीय चुनाव के बाद राज्य में जद (यू)-भाजपा के गठबंधन का परिणाम था। बिहार में जद (यू)-भाजपा गठबंधन ने 2005 में लालू प्रसाद यादव के पंद्रह साल के शासन को हराया और तब से 2013 से 2017 को छोड़कर सत्ता में बने हुए हैं।

"बिहार की राजनीति किसी भी सरल भविष्यवाणी को नकारती है क्योंकि यह उन राज्यों में से एक है जो विकास सूचकांक में नीचे है लेकिन राजनीतिक चेतना में बहुत ऊपर है"। भारत की आजादी के बाद के दशकों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका नेतृत्व ज्यादातर उच्च जातियों ने किया, बिहार पर शासन किया। जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल विरोधी आंदोलन बिहार में जातीय गठबंधन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1990 के राज्य विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत ने बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ओबीसी राजनीति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, दोनों क्रमशः बिहार में दो अलग-अलग समुदायों- यादव और कुर्मी का प्रतिनिधित्व करते थे। मणिंद्र ठाकुर ने ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित 'बिहार राजनीति की जटिलता' शीर्षक वाले अपने पेपर में कहा है कि 'ओबीसी के दोनों गुट तब तक राजनीति में एकजुट रहे जब तक राज्य में उच्च जाति एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी रही लेकिन एक बार उच्च जाति मैदान से बाहर हो गई , उनके बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई और लोहिया और जय प्रकाश नारायण के दोनों शिष्यों ने जाति समूहों के अलग-अलग गुट बनाए।' वह बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के जातीय गठबंधन पर जोर देते हैं। उनकी

राय में राज्य में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी अपना सामाजिक आधार खो चुकी है. विशेष रूप से उच्च जाति का समर्थन भाजपा की ओर स्थानांतरित हो गया क्योंकि ओबीसी पहचान पर आधारित पार्टियों ने उच्च जाति को कोसने पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी और कांग्रेस के पास उन्हें इस हमले से बचाने की कोई क्षमता नहीं थी। लालाउ प्रसाद यादव के "भूरा बाल साफ करो" जैसे नारे का अर्थ है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को राजनीति से हटाओ और बाद में "भूमिहार को साफ करो, ब्राह्मण को आधा करो और लाला को माफ करो" का अर्थ है (भूमिहार को खत्म करो, ब्राह्मणों को समायोजित करो) आंशिक रूप से और माफ कीजिए लाला) ने बिहार में ऊंची जाति के वर्चस्व को चुनौती दी।

कांग्रेस के पतन के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद बड़ी पार्टी बनकर उभरी. जनता दल की राज्य इकाई में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, उन्होंने 1990 के राज्य विधानसभा चुनाव में 270 सीटों में से 100 यादवों को उम्मीदवार के रूप में नामित किया और वह यादवीकरण को कायम रखने के बारे में बहुत खुले और मुखर थे। संजय कुमार 1990 के दशक के बाद के काल को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में ओबीसी राजनीति के उद्भव के काल के रूप में परिभाषित करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा में पार्टी संरचना और राज्य की राजनीति में यादवीकरण को कायम रखने के आरोपों की निंदा की है और कहा है कि "मैंने गरीब लोगों को आवाज दी, वे इसे गुंडा राज कहते हैं" (गरीबों को दी आवाज तो उसको कहा गुंडा राज)।

संकर्षण ठाकुर के अनुसार, दूसरी ओर नीतीश कुमार खुद को किसी भी जाति समूह के सामने उजागर करने में बहुत अनिच्छुक थे। जाति की राजनीति से घृणा के कारण वे कुर्मी चेतना महारैली में जाने से बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर लालू प्रसाद यादव इस समय अपनी जाति के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो कुर्मी उन्हें जाति से बहिष्कृत घोषित कर देंगे। जद में यादवों को बढ़ावा देना। जद (यू)-भाजपा का गठबंधन बिहार में लालू विरोधी

गोलबंदी का प्रतीक बन गया और दोनों दल कोइरी-कुर्मी वोट को नीतीश कुमार के पक्ष में और उच्च जाति के समर्थन को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में सफल रहे। संजय कुमार ने 1990 के दशक के चुनावों के बाद बिहार में विभिन्न जातियों के मतदान पैटर्न में बदलाव पर प्रकाश डाला है।

यद्यपि जातिवाद की घटना बिहार में भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट है, जैसा कि सुमित्रा कुमार जियान ने कहा है, 2010 के विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम ने कई राजनीतिक टिप्पणीकारों के दृष्टिकोण को बदल दिया है। संजय कुमार कहते हैं कि "कई राजनीतिक टिप्पणीकार जिन्होंने अतीत में बिहार में चुनावी राजनीति का सारांश केवल जाति-आधारित मतदान के संदर्भ में दिया था, अब यह निष्कर्ष निकाला है कि 2010 का विधानसभा चुनाव केवल विकास के बारे में था और कुछ नहीं"।

अनिल सिंह ने बिहार के विकास मॉडल की सराहना करने वाले पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर की टिप्पणी को बहुत प्रभावशाली बताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बिहार में किए गए कार्यों को लेकर पाकिस्तान में काफी दिलचस्पी है. हालांकि बिहार में व्यक्ति के मतदान व्यवहार के अलग-अलग पैटर्न के कारण जाति बनाम विकास की बहस अभी खत्म नहीं हुई है. 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम ने जाति और विकास कारक को एक साथ मजबूत कर दिया और राज्य में जद (यू)-राजद-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ भाजपा की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। एक साल पहले लोकसभा चुनाव ने एक अलग परिणाम दिखाया था जिसमें भाजपा ने अकेले 22 सीटें हासिल की थीं और दूसरी ओर जद (यू) केवल 2 सीटें जीत सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जद (यू)-भाजपा का गठबंधन हुआ था, जो परिणामस्वरूप राज्य में भारी जीत हुई और गठबंधन को 40 में से 39 सीटें हासिल हुईं।

किसी भी घटना, परिघटना या विकास की व्यवस्थित व्याख्या के लिए विशाल साहित्य की आवश्यकता होती है। जबकि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा और बिहार में उनके राजनीतिक शासन के मॉडल पर कई किताबें, लेख, कॉलम और पेपर प्रकाशित हुए हैं, जनता दल (यूनाइटेड) की उत्पत्ति और विकास पर मेरी सीमित जानकारी के अनुसार अकादमिक जगत में ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। साहित्य। इसलिए, पटना साइंस कॉलेज में एक इंजीनियर से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में बहुत सारा साहित्य चर्चा करता है। इस श्रेणी में पाया गया पहला प्रमुख काम 2011 में अरुण सिन्हा द्वारा लिखित "नीतीश कुमार और बिहार का उदय" था। अरुण सिन्हा मूल रूप से बख्तियारपुर से बिहार के मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करते हैं। इसी तर्ज पर संकर्षण ठाकुर ने नीतीश कुमार के जीवन के विभिन्न चरणों को समझाने की कोशिश की है और यह भी बताया है कि नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें क्या बदलाव देखने को मिले। संकर्षण ठाकुर ने अपनी पुस्तक 'सिंगल मैन: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार' में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन और उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है और बाद में उनके व्यक्तिगत विश्वास और विचारधारा ने उनके राजनीतिक कैरियर पर कैसे प्रभाव डाला है। .

लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा "गोपालगंज टू रायसीना: माई पॉलिटिकल जर्नी" में एक अध्याय नीतीश कुमार को समर्पित किया है जिसमें उन्होंने उन्हें 'छोटा भाई नीतीश' कहा है। इस अध्याय में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं और उन्हें अवसरवादी बताते हैं, जिन्होंने सत्ता के लिए राज्य में बीजेपी से हाथ मिलाकर विचारधारा से समझौता कर लिया.

1990 के दशक के बाद बिहार की राजनीति को समझने के लिए संजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक "पोस्ट-मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार: चेंजिंग इलेक्टोरल पैटर्न" बहुत उपयोगी है। इस

पुस्तक में संजय कुमार ने बिहार में पहले लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में और बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ओबीसी राजनीति की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या की है। उन्होंने राज्य में विभिन्न चुनावों और मतदान के पैटर्न को व्यवस्थित रूप से समझाया है और राज्य में विभिन्न दलों के भीतर नेतृत्व संरचना को भी समझाया है। बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रकृति को समझने के लिए जाति, विकास और लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार के करिश्माई व्यक्तित्व की भूमिका को बहुत अच्छे से समझाया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर चर्चा किए गए अध्ययनों ने बिहार में विशेष रूप से 1990 के बाद के राजनीतिक शासन की हमारी समझ में योगदान दिया है, लेकिन जद (यू) की उत्पत्ति, सामाजिक आधार, नेतृत्व संरचना, विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों की व्यवस्थित व्याख्या गायब थी। पहले के लेखों में बिहार में कांग्रेस शासन और बाद में राजद शासन पर बहुत जोर दिया गया था और बिहार में जद (यू) की भूमिका का विश्लेषण करने के कुछ प्रयास किए गए थे। वैसे तो नीतीश कुमार पर कई लेख मिलते हैं लेकिन जद (यू) के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता. वर्तमान कार्य बिहार में जद (यू) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की एक व्यवस्थित व्यापक तस्वीर प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. 1990- 2020 तक बिहार में राजनीतिक शासन की उत्पत्ति, विकास और प्रकृति का पता लगाना।

2. बिहार में जद (यू) के उद्भव, विकास, वैचारिक रुख और नेतृत्व के पैटर्न की जांच करना।

3. राज्य विधानसभा चुनावों में 2004 से 2020 तक जद (यू) की लामबंदी रणनीतियों और चुनावी प्रदर्शन की पहचान करना।

परिकल्पना

(क) क्षेत्रीय दलों के अविर्भाव ने गठबंधन की राजनीति को अपरिहार्य बना दिया है

(ख) क्षेत्रीय दलों के शासन ने राजनीतिक स्थायित्व प्रदान की है

(ग) जद (यू) के शासन ने बिहार में सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया है

(घ) भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, क्षेत्रीय चेतना और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के साथ अपनी क्षेत्रीय पहचान से संबद्ध है

(ङ) क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन कायम करने का एक कारगर प्रयास है

अनुसंधान प्रश्न

1. देश में मंडल आंदोलन की लहर और 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम किस तरह बिहार की राजनीति को प्रभावित किया ?

2. जनता दल से अलग होने के बाद समता पार्टी/जेडी (यू) एक पार्टी के रूप में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कैसे उभरी?

3. 2004-2020 राज्य विधानसभा चुनाव में जद (यू) की जीत के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं?

4. जद (यू) में एक पार्टी सदस्य और एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की क्या भूमिका और योगदान है?

5. जद (यू) की प्रमुख नीतियां क्या हैं जिन्होंने (2005-2020) से बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदल दिया।

पद्दतियाँ

अध्ययन में अपनाई गई विधियाँ मूलतः ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक हैं। "वर्णनात्मक अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत एक अध्ययन किसी स्थिति, समस्या, घटना, सेवा या कार्यक्रम का व्यवस्थित रूप से वर्णन करने का प्रयास करता है या समुदाय की रहने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, या किसी मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन करता है"। ऐसे अध्ययनों का मूल उद्देश्य यह वर्णन करना है कि अध्ययन के तहत समस्याओं/मुद्दों के संबंध में क्या प्रचलित है। अध्ययन के आंकड़े द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं। जहां भी आवश्यक हो, तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान किया गया है। अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विचार और संसाधन प्राप्त करने के लिए बिहार विधान सभा की बहसें, संबंधित दलों के राजनीतिक नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं और अन्य राजनीतिक दलों पर प्रकाशित अन्य साहित्यिक कृतियों का उपयोग किया गया है। विषय-वस्तु से संबंधित प्रकाशित समसामयिक समाचार-पत्र एवं पत्रिका का भी आवश्यक जानकारी एवं आँकड़े एकत्र करने में उपयोग किया गया है। अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों की मदद से बिहार के राष्ट्रीय और राज्य चुनाव दोनों सहित चुनावी परिणामों का भी विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रासंगिक पुस्तकों और पत्रिकाओं का उपयोग अध्ययन के लिए किया गया है जो राज्य की राजनीति, गठबंधन की राजनीति और भारत में क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका से संबंधित हैं। अध्ययन के लिए समय और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुछ प्राथमिक जानकारी एकत्र करने के लिए पार्टी प्रतिनिधि का साक्षात्कार एक विकल्प था, जिसे मैं सीमित संसाधनों और समय के कारण नहीं कर सका।

अध्यायीकरण

वर्तमान कार्य एक व्यवस्थित समझ प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है

अध्याय 1 : परिचय

अध्याय 2 : 1990-2020 तक बिहार में पार्टियाँ और राजनीति

अध्याय 3 : जनता दल (यूनाइटेड) का उदय एवं **राजनीतिक स्थायित्व**

अध्याय 4 : 2005-2020 जद (यू) का चुनावी प्रदर्शन एवं **सुशासन** का प्रयोग

अध्याय 5: निष्कर्ष

ग्रंथ सूची

संदर्भ:

प्राथमिक स्रोत :

तकनीकी प्रतिवेदन

मंडल कमीशन रिपोर्ट

दस्तावेज़ों का संग्रह

व्यक्तिगत साक्षात्कार

संस्मरण

द्वितीयक स्रोत

1. श्रीधरन, ई और डिसूजा, पी. आर (2006), इंडियाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. रामलिंगप्पा, के (2011), भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल: आंध्र प्रदेश में तेलगु देसम पार्टी पर एक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, अनंतपुर: श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय।

3. शर्मा, एस (1995), स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, नई दिल्ली: मित्तल प्रकाशन।

4. शेट्टी, बी.एन. (2009), उड़ीसा में पार्टियाँ और राजनीति: बीजू जनता दल का एक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

5. अनिल सिंह (2013), 'बिहार: कैओस टू कैओस', नई दिल्ली: हिंदुस्तान पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।

6. कुमार, एस (2018), 'पोस्ट मंडल-पॉलिटिक्स इन बिहार: चेंजिंग इलेक्टोरल पैटर्न', नई दिल्ली: ऋषि प्रकाशन इंडिया प्रा. लिमिटेड, पृष्ठ संख्या Xxii

7. शेट्टी, बी.एन. (2009), ओडिशा में पार्टियाँ और राजनीति: बीजू जनता दल का एक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

8. पाई, एस (1990), 'रीजनल पार्टीज़ एंड द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया', द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 51 (3): 13।

9. रामलिंगप्पा, के (2011), भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल: आंध्र प्रदेश में तेलगु देसम पार्टी पर एक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, अनंतपुर: श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय। पृष्ठ संख्या 59-60.

10. शेट्टी, बी.एन. (2009), उड़ीसा में पार्टियाँ और राजनीति: बीजू जनता दल का एक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

11. पाटिल, एस.एच. (2001), 'संघीय स्तर पर गठबंधन सरकार के साथ भारत का प्रयोग', द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 62 (4): 587।

12. झा, पंकज कुमार. (2010), सुशासन के आईने में नया बिहार, प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ संख्या, 272।

13. सिन्हा, अरुण (2011) नीतीश कुमार और बिहार का उदय (Nitish Kumar and the Rise of Bihar), पेंगुइन प्रकाशन ।

Sanjay Kumar Suman

शोधकर्ता के हस्ताक्षर

15/4/24

15/04/2024

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

20.04.24

20/4/24

M.Kumar 20.4.24

MB Verma 20.04.2024